(d) the outcome of the investigation, if any, made into these cases; and

(e) the remedial measures taken to prevent such fraudulent dealings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (e) The enquiries into certain cases of exports made under Rupee Trade arrangements and suspected to have been diverted to hard currency area and its modus operandi, are at preliminary stage. Disclosure of details at this stage would effect the inquiries. The enforcement agencies are vigilant for apprehending the offenders.

Colloquium on Foreign Trade, GATT and Third World Development

1183. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the decision taken by the Colloquium on foreign trade, GATT and Third World Development held at Bangalore in July 1991;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Yes, Sir. The National Working Group on Patent Laws, in collaboration with the National School of India University, Bangalore, organised a Colloquium on 'Foreign Trade, GATT and Third World Development' on 27 and 28 July, 1991. The resolution adopted at the Colloquium concerned the areas of intellectual property, rights, investment measures, services, trade in agriculture and related matters. These issues are being negotiated in the Uruguay Round. There are many different perceptions on these issues among participants and no degree of finality has been arrived at. Government will continue to strive to obtain the most advantageous outcome for India.

Textile Mills in Maharashtra

1184. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the number of textile mills in Maharashtra; and

(b) what is the number of proposals to set up the Co-operative Spinning Mills from Maharashtra are pending with Union Government for the clearance of licences and what is the latest position?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) In Maharashtra State there are 122 Textile Mills.

(b) No proposal is pending for setting up of Co-operative Spinning Mills from Maharashtra State in the Ministry of Textiles, therefore question for clearance of licences does not arise.

औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाएं

1185. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन-कौन सी हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा राज्य-वार कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई नीतियों के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया है ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्थाओं को इस भेदभावपूर्ण नीति को बदलने के लिए कोई

निर्देश जारी किए हैं ; यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को अधिक विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऋण दिलवाने के संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जहां आवश्यक हो, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण-बीमा निगम और वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर चयनात्मक आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं को मध्यावधि और दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । राज्य स्तरीय संस्थाएं भी औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई राज्य-वार सहायता अनुपत्र में दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट CLX, परिपत्र सं० 50]**

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यथासंभव रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के साथ उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रमों, तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों की स्थापना तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के जरिए, खासकर अधिक दृष्टि से अविकसित क्षेत्रों में उद्यमिता संबंधी गतिविधियों के उच्च स्तर को बढ़ावा देता आ रहा है । पिछड़े क्षेत्रों में दिये गये ऋणों में लगातार वृद्धि हुई है । औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर नये सिरे से जोर देने की दृष्टि से संस्थाओं ने परियोजना/आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण नये उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित मझौली परियोजनाओं के लिए इक्विटी समर्थन के प्रावधान और राज्य सरकारों तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं के सुनिश्चित सक्रिय सहयोग के द्वारा उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रमों पर नवीकृत बल देने जैसे कुछ उपाय अपनाने का निर्णय लिया है । उक्त उपायों से पिछड़े और अन्य क्षेत्रों में बेहतर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने में आसानी होगी ।

Specialist Doctors demand for Modification in Tikku Committee Report

1186. SHRI MAHENDRA PRASAD:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Specialist Doctors Federation of Central Health Services staged a silent march on 31st July, 1991 and have been protesting to press their demands for modifications in the recommendations of the Tikku Committee;

(b) if so, what modifications the Federation has been striving for; and

(c) what is Government's stand on these recommendation demands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Yes, Sir.

(b) The Specialist Officers Association of Central Health Service in their letter dated 29|31-7-91 have requested certain modifications in the recommendations of the Tikku Committee Report. The important modification proposed by them relate to parity in the Specialists Sub-cadres, 3 time-scale promotions with lesser number of years of service, conversion of posts in the scale of Rs. 4500-5700(Functional) to Senior Administrative Grade (Rs. 5900-7300), recruitment in Specialist Cadre by open selection through Union Public